

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (गढ़वाल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून। दिनांक : २४ फरवरी, 2017

विषय: केन्द्र पोषित "Upgradation of Existing Polytechnics" योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त अंतिम किश्त की धनराशि को व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-490/XXVII-I/2016 दिनांक 31.03.2016, शासनादेश संख्या-847/XXVII-I/2016 दिनांक 26.07.2016, 1097/XXVII-I/2016 दिनांक 20.09.2016, शासनादेश संख्या-132/XLI-1/2015-123/2011 दिनांक 20.02.2015, शासनादेश संख्या-217/XLI-1/2015-123/2011 दिनांक 24.03.2015, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के शासनादेश संख्या-16-2/2015-TS.IV(Gen) दिनांक 07.10.2016, शासनादेश संख्या 16-2/2015-TS.IV(SC) दिनांक 07.10.2016, शासनादेश संख्या-16-2/2015-TS.IV(ST) दिनांक 07.10.2016 एवं आपके पत्र संख्या-796/नि.प्रा.शि./अपग्रेडेशन/2016-17 दिनांक 26.10.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत राजकीय पॉलीटैक्निक, गौचर, रा०पा० उत्तरकाशी, रा०पा० द्वाराहाट व रा०पा० सल्ट में मशीनों/सज्जा/उपकरणों आदि के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा अंतिम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि क्रमशः ₹ 40.00 लाख, ₹ 33.00 लाख, ₹ 46.00 लाख एवं ₹ 24.00 लाख कुल ₹ 143.00 लाख (₹ एक करोड़ तौंतालिस लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार नीचे दी गयी सारणी के अनुसार धनराशि आहरित कर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

क्र. सं.	पॉलीटैक्निक का नाम	धनराशि (लाख ₹ में)			
		सामान्य	अनु.जाति	अनु.ज.जाति	योग
1	राजकीय पॉलीटैक्निक, गौचर	31.000	6.000	3.000	40.000
2	राजकीय पॉलीटैक्निक, उत्तरकाशी	25.575	4.950	2.475	33.000
3	राजकीय पॉलीटैक्निक, द्वाराहाट	35.650	6.900	3.450	46.000
4	राजकीय पॉलीटैक्निक, सल्ट	18.600	3.600	1.800	24.000
	योग	110.825	21.450	10.725	143.000

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए भारत सरकार के उक्त संदर्भित शासनादेशों में निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उन्ही मदों के लिए किया जायेगा, जिसके लिए उपरोक्त सारणी में स्वीकृति दी जा रही है।
3. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु केन्द्रांश अवमुक्त करने हेतु निर्धारित अनुपात में ही संबंधित श्रेणियों में व्यय किया जाएगा जिससे संबंधित सैकटर को लक्षित लाभ की प्राप्ति हो सके।
4. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्यिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. कम्प्यूटर आदि क्रय के पूर्व एन.आई.सी./आई.टी. विभाग की नियमानुसार संस्तुति प्राप्त कर ली जायेगी।
7. फर्नीचर/उपकरण/कम्प्यूटर आदि के आवंटन के समय नियमानुसार निर्धारित मानकों, अनुमन्यता एवं न्यूनतम आवश्यकता का परीक्षण कर लिया जाएगा।
8. उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
9. यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त संस्थाओं में उक्त योजनान्तर्गत क्रय किए गये मशीनरी/उपकरणों आदि का किसी अन्य मद/योजना से भी क्रय न कर लिया गया हो। इस प्रकार दोहराव को निषिद्ध करने हेतु संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार एवं शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
11. मितव्यिता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. वर्तमान में राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू होने के दृष्टिगत फर्नीचर/उपकरण/कम्प्यूटर आदि क्रय किये जाने हेतु आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय-व्ययक में ‘आयोजनागत पक्ष’ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2203–तकनीकी शिक्षा–105–बहुशिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0102– राजकीय बहुधंधी संस्थाओं का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण” के अन्तर्गत मानक मद “26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र” के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश शासनादेश संख्या–183/xxvii-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर

/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या संलग्नक-1 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेशों दिनांक 31.03.2016, दिनांक 26.07.2016 एवं दिनांक 20.09.2016 के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

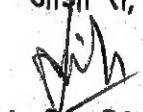
भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : २२३ (1) / XL(1) / 2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. अनुसंचिव, भारत सरकार TS.IV, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/चमोली/उत्तरकाशी।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/चमोली/उत्तरकाशी।
6. संबंधित प्रधानाचार्य।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उप सचिव।